WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

कृषि क्षेत्र में हरित क्रान्ति

*141. **श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला:**
श्री अजीत जोगी:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में हरित क्रान्ति लाने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1997-98 के लिए कृषि उत्पादन के लिए निर्धारित फसल-वार और मद-वार लक्ष्य क्या है;

(घ) वर्ष 1996-97 के कुल निर्धारित लक्ष्य में से कितने प्रतिशत कृषि उत्पादन का अनुमान लगाया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) से (ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव संबंधी दस्तावेज में कृषि क्षेत्र की नीति के अन्तर्गत "हरित क्रान्ति" का कोई उल्लेख नहीं है। तथापि, नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1997—2002) में कृषि क्षेत्र के लिए 4.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की परिकल्पना की गई है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई जा रही विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को नौवीं योजना के दौरान भी जारी रखा जा रहा है। तथापि, नौवीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। इसके अतिरिक्त, नौवीं योजना के दौरान, कृषि के विकास में और अधिक तेजी लाने के लिए कई नए उपाय किए जाने का प्रस्ताव है, विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में, जहां उत्पादकता का स्तर न्यून है और क्षमता अधिक है। प्रस्तावित रूप से किए जाने वाले कुछ प्रमुख नवीन उपाय निम्नानुसार हैं:—

(1) पूर्वी राज्यों में उत्पादकता बढ़ाने के उपायों में इन कार्यक्रमों का पैकेज है—(क) ऑन-फार्म जल प्रबन्ध; (ख) कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना; (ग) उर्वरक की खपत में वृद्धि; और (घ) सहकारी ऋण संरचना में सुधार और उसे पुनः सक्रिय बनाना।

(2) कपास के बारे में एक प्रौद्योगिकी मिशन का गठन;

(3) एक नई प्रायोगिक फसल बीमा योजना शुरू करना;

(4) सहकारी ऋण संरचना के नवीकरण/सुधार का कार्यक्रम।

निम्न तालिका में वर्ष 1996-97 के उत्पादन के लक्ष्यों और अनुमानित उत्पादन को दर्शाया गया है:

फसल	लक्ष्य	अनुमानित उत्पादन	लक्ष्यों की तुलना में अनुमानित उत्पादन—वृद्धि का प्रतिशत
खाद्यान्न (मिलियन टन)	193.5	198.96	2.8
तिलहन (लाख टन)	230.0	251.6	9.4
कपास (लाख गांठे)	130.0	142.5	9.6
पटसन एवं मेस्ता (लाख गांठे)	90.0	110.0	22.2
गन्ना (लाख टन)	2700.0	2767.5	2.5

वर्ष 1997-98 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, इसके 200 और 202 मिलियन टन के बीच निर्धारित होने की संभावना है।

अन्य मुख्य फसलों के मामले में, योजना आयोग द्वारा निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:—

तिलहन	25.5 मिलियन टन
गन्ना	280.0 मिलियन टन
कपास	14.8 मिलियन गांठे
पटसन व मेस्ता	9.75 मिलियन गांठे

कृषि उतपादकता को बढ़ाने में राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए भारत सरकार द्वारा कई केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। वर्ष 1997-98 के दौरान, विशिष्ट रूप से फसल उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए, निम्न फसलोन्मुख योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं:

(1) चावल आधारित फसल पद्धति क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम;

(2) गेहूं आधारित फसल पद्धति क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम;

(3) मोटे अनाज आधारित फसल पद्धति क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम;

(4) गहन कपास विकास कार्यक्रम;

(5) विशेष पटसन विकास कार्यक्रम;

(6) गन्ना आधारित फ़सल पद्धति का सतत् विकास;

(7) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम; और

(8) राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना।

Cleaning of the Yamuna River

*142. DR. D. VENKATESHWAR RAO:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of ENVIRONMENT & FORESTS be pleased to state:

(a) the details of actions taken to control pollution of the Yamuna river; and

(b) the target date fixed to complete the cleaning of river and the cost involved?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) and (b) To control pollution of the Yamuna river, a programme called the Yamuna Action Plan was approved by Government in April, 1993. Under this Plan, pollution abatement works have been taken up in 12 towns in Haryana and 8 towns in Uttar Pradesh besides Delhi. The programme covers such works as interception & Diversion of sewage outfalling into the river, treatment of intercepted sewage, construction of low cost toilets, crematoria and bathing ghats, river front development, plantation along the river and public participation. A sewage treatment capacity of 736 million litres per day has been sanctioned under the plan. The present approved cost of the Yamuna Action Plan is Rs. 479.56 crore. In addition, the Government of National Capital Territory of Delhi has taken up a programme for augmentation of sewage treatment capacity in Delhi from the present 1270 million litres per day to 2270 million litres per day at an estimated cost of around Rs. 260 crore. The target date for completion of the Yamuna Action Plan work is 31.03.1999 whereas that for the treatment works taken up by the Government of National Capital Territory of Delhi is December, 1999.

To control industrial pollution directions have been issued under Section 18(1)(b) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 to the State Pollution Control Boards/Committees to issue notice to the defaulting industries which are directly discharging effluents into rivers and lakes giving 3 months time for complying with the prescribed discharge standards or face closure.

National Culture Fund

*143. SHRI AKHILESH DAS: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Culture Fund set up as a key instrument to revive and encourage people's